

हर दिन को अपनी जिंदगी का पहला दिन समझकर लिए।

- अज्ञात

## वायरस के कहर की मिसाल

सत्र शुरू होने से पहले करवाए गए कोरोना टेस्ट में 25 सांसद पॉजिटिव पाए गए। दिलचस्प मामला राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल का है जो संसद भवन में हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर लौट गए।

नवीन वर्मा।।

देश में कोरोना के तेज फैलाव के बीच शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र इस वायरस के कहर की मिसाल बन गया। सत्र शुरू होने से पहले करवाए गए कोरोना टेस्ट में 25 सांसद पॉजिटिव पाए गए। दिलचस्प मामला राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल का है जो संसद भवन में हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर लौट गए। राजस्थान पहुंचकर उन्होंने जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में फिर से जांच करवाई तो वहां उन्हें नेगेटिव बताया गया। उन्होंने दोनों रिपोर्टों की कॉपी ट्वीट करते हुए पूछा है कि किसे सही माना जाए।

सोमवार को ही दिल्ली विधानसभा का भी एकदिवसीय सत्र हुआ। उसके लिए करवाए गए टेस्ट में चार एमएलए पॉजिटिव

पाए गए। लेकिन वहां की खास बात यह रही कि दो ऐसे विधायक रहे जो एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव बताए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए लेकिन शाम को उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आया तो वे पॉजिटिव थे। उसके बाद दोनों विधायक सदन से चले गए, लेकिन दिन भर तो वे कोरोना नेगेटिव विधायक की तरह सभी गतिविधियों में शामिल रहे। इन स्थितियों ने एक बार फिर देश का ध्यान इस बात की तरफ ध्यान खींचा है कि कोरोना से निपटना तो दूर, उससे बचाव को लेकर भी कोई फूलप्रूफ प्रक्रिया हम नहीं अपना पा रहे। इसके जो दो तरह के टेस्ट प्रचलित हैं— रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर, उनमें आरटी-पीसीआर को ही भरोसेमंद माना जाता है। ब्लड

सैंपल लेकर किए जाने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आ जाती है और यह टेस्ट कम खर्चीला होता है। लेकिन इसकी रिपोर्ट की प्रामाणिकता 50 फीसदी ही बताई जाती है।

आरटी-पीसीआर टेस्ट जिसमें नाक और गले से स्वीब के नमूने लिए जाते हैं, प्रामाणिक तो माना जाता है लेकिन लैब, टेक्नीशंस और मशीनों से जुड़ी सीमाओं के चलते हमारे यहां इसकी संख्या एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। इसका महंगा होना अलग समस्या है। एक टेस्ट पर करीब 4500 रुपये का खर्च आता है। शायद इसीलिए अपने देश में बड़े पैमाने पर टेस्ट करने के जो दावे विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से आ रहे हैं, वे एंटीजन टेस्ट के ही हैं। ऐसे में लगभग छह करोड़ टेस्ट के बावजूद

अगर महामारी नियंत्रित होती नहीं नजर आ रही तो खास आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि महामारी के बेरोकटोक बढ़ने की खबरें सिर्फ अपने देश से नहीं आ रही। कई यूरोपीय देशों में इसकी दूसरी लहर चल पड़ने का खौफ दिखाई दे रहा है। इजरायल में एक बार लॉकडाउन हटा लिए जाने के बाद फिर कम से कम तीन सप्ताह के लिए इसे लागू करने का फैसला किया गया है। बहरहाल, अभी पूरी दुनिया में कोरोना का सबसे भयावह रूप हमारे यहां देखा जा रहा है और रोजाना संसार के एक तिहाई मरीज भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। 50 लाख से ऊपर कुल संक्रमण और 90 हजार प्रतिदिन नए संक्रमितों के आंकड़े हमें इस मोर्चे पर किसी भी तरह की ढिलाई की इजाजत नहीं दे रहे।

## युद्ध और शान्ति

अशोक वोहरा।

मनुष्य को स्वभाव, कर्म व गुणों के आधार पर शान्त प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतरी भाग में

धर्म-दर्शन



कहीं-न-कहीं एक हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। परन्तु मनुष्य का भरसक प्रयत्न रहता है कि वह भीतर का हिंसक प्राणी किसी प्रकार भी जागे नहीं। यदि किसी कारणवश वह जाग पड़ता है तो तरह-तरह की संघर्षात्मक क्रिया-प्रक्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का जन्म होने लगता है, तब उनके घर्षण तथा प्रत्याघर्षण से युद्धों की ज्वाला धधक उठती है। इस प्रकार के युद्ध यदि व्यक्ति या व्यक्तियों के मध्य होते हैं तो वे गुटीय या साम्प्रदायिक झगड़े कहलाते हैं। परन्तु जब इस प्रकार के युद्ध दो देशों के मध्य हो जाते हैं तो वे कहलाते हैं। युद्ध। गुफा के बाहर दो कबूतर रहते हैं, जो शिव के पार्षद कहलाते हैं।

## संपादकीय

### आपदा में अवसर

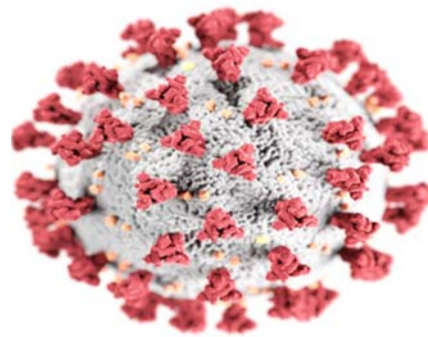
विपक्ष को कोरोना काल में समस्याओं से घिरी सरकार को घेरने और खुद को राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में लाने का मौका दिख रहा है। पिछले साल आम चुनाव में पहले से भी बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली मोदी सरकार ने दूसरे टर्म के पहले ही सत्र में संसद के अंदर और बाहर आक्रामक राजनीति करने की अपनी मंशा दिखा दी थी। संसद के अंदर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और तीन तलाक से जुड़े बिल पास कराए गए। सत्ता पक्ष ने राज्यसभा में भी उसने अपनी स्थिति मजबूत की। बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि बहुमत की ताकत के साथ एनडीए सरकार शुरू से ही फ्रंट फुट पर खेलेगी और विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। यह दबाव अभी तक दिखा भी है। न सिर्फ विपक्षी दलों के बीच सामंजस्य बिखर गया बल्कि कई विपक्षी नेता बीजेपी के पाले में भी गए। हालांकि विपक्ष को इस सत्र में इस ट्रेंड के बदलने की उम्मीद दिख रही है। ऐसे में संसद के मानसून सत्र के दौरान सबसे अधिक ऐसे क्षेत्रीय दलों के रुख पर नजर रहेगी, जो हाल के सालों में एनडीए से नजदीकी दिखाते रहे हैं। क्षेत्रीय दलों ने कई मौकों पर अहम बिलों को पास कराने में मोदी सरकार की मदद भी की थी। मानसून सत्र में मोदी सरकार को खासकर इन दलों के सहयोग की अपेक्षा राज्यसभा में रहेगी। वहीं विपक्षी दल की एकजुटता का भविष्य क्या होने वाला है, यह भी सत्र के दौरान सामने आएगा। कई मौकों पर विपक्षी एकजुटता की अपील के बाद भी कुछ राज्यों को छोड़कर कहीं भी राजनीतिक दल एकजुट नहीं हो पाए थे।

सरकार और विपक्ष, दोनों सत्र शुरू होने से पहले अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। सरकार ने अपने अजेंडे को पूरा करने के लिए विपक्ष को विश्वास में लेने की भी कवायद की है।

## अजेंडा बनाम मुद्दा

नरेंद्र नाथ ।।

कोरोना आपदा के बीच संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। यह सत्र कई मायनों में अनूठा होगा। महामारी के बीच कई तरह की बंदिशों और नए प्रयोग के बीच होने वाले इस संसद सत्र में हालांकि बहुत ही सीमित और जरूरी काम होने की संभावना दिख रही है, लेकिन सियासत की बारिश में किसी तरह की कमी होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। सरकार और विपक्ष, दोनों सत्र शुरू होने से पहले अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। सरकार ने अपने अजेंडे को पूरा करने के लिए विपक्ष को विश्वास में लेने की भी कवायद की है। कोरोना के कारण संसद का बजट सत्र भी बीच में ही रोक दिया गया था। इस बार भी कोविड-19 के विकराल स्वरूप के बीच जब संसद का सत्र हो रहा है, तो कई तरह के एहतियात होंगे। 18 दिनों तक चलने वाले सत्र में हर दिन आठ घंटे काम होगा, जिसमें 4 घंटे लोकसभा तो 4 घंटे राज्यसभा के लिए आरक्षित होंगे। इसी दौरान सारे जरूरी काम निपटाए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांसद एक जगह न बैठकर, अलग-अलग बैठेंगे। कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। इस बार दर्शक भी नहीं आएंगे तो मीडिया को भी सीमित एंट्री मिलेगी।



सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान 23 बिलों को पास करने का अजेंडा पेश किया है। इनमें 11 ऑर्डिनंस बिल हैं, जिन्हें बजट सत्र के बाद कैबिनेट ने मंजूरी दी है और अब संसद से इसका अनुमोदन लेना जरूरी है। इसमें एक ऑर्डिनंस स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम से जुड़ा है। कोरोना के समय डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हो रहे हमले के बीच इसे पेश किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ हिंसक मारपीट और उन्हें परेशान करने के कार्यों को गैर जमानती अपराध करार दिया गया है। इसमें अधिकतम सजा सात साल जेल और पांच लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। वहीं एक बिल कोविड के समय आर्थिक संकट से बचने के लिए एक साल के लिए सांसदों

के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती करने से जुड़ा है। जिस ऑर्डिनंस पर सबसे अधिक विवाद होने की उम्मीद है, वह है सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के दौरान किसानों के लिए पेश किया गया नया कानून। किसानों के लिए दावा किया गया है कि नए कानून के बाद वे अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और उन्हें मंडियों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें कई और भी प्रावधान हैं, जिसका कि किसान विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को इस बिल में अब भूमि अधिग्रहण बिल जैसी स्थिति दिख रही है, जिसमें धीरे-धीरे विरोध बढ़ने लगा था। विपक्ष इस बिल को किसान विरोधी और कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बता रहा है। विपक्ष ने इसे अंतिम समय में सत्र के दौरान सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का संकेत दिया है। वहीं कोरोना के बाद केंद्र सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदम, चीन के साथ सीमा विवाद, गिरिटी जीडीपी का मुद्दा भी इस बार सत्र के दौरान उठेगा, जिस पर विपक्ष आक्रामक हो सकता है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी इस सत्र के दौरान कोविड के बाद सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और आगे के रोडमैप पर भी विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। लेकिन चीन के मुद्दे पर सरकार बहस करेगी, या सिर्फ बयान देगी, अभी इस बारे में कुछ साफ नहीं है।

सूचीक नवताल-5476						* * * * *									
दल						दल									
7	9	4	2	6	3	8	5	1	3	7	2	4	6		
6		8		7	2	7	3	2	6	5	4	1	8	9	
4	1			3	5	8	1	6	4	8	9	2	7	5	3
9	8	3					5	7	3	4	2	9	6	1	8
7	4		5	8	1	4	2	8	5	6	1	3	9	7	
				9	7	3	6	1	9	3	7	8	5	2	4
8	5	7					3	5	1	9	4	8	6	7	2
2	9		1	5			2	4	6	7	8	5	9	3	1
3	1		6	8	9	7	9	8	7	2	1	3	4	6	5

### अपना ब्लॉग

विपक्ष को दो मौके भी मिलेंगे

**मोहन।** मानसून सत्र विपक्षी एकजुटता के लिए नई कोशिश का अच्छा अवसर हो सकता है। इसके लिए विपक्ष को दो मौके भी मिलेंगे। पहला मौका होगा राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव का। इसमें एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हरिवंश खड़े हैं, तो विपक्ष ने अपना साझा उम्मीदवार आरजेडी सांसद मनोज झा को बनाया है। दोनों बिहार के ही हैं। हालांकि हरिवंश के जीतने की संभावना अधिक है, लेकिन विपक्ष ने साझा उम्मीदवार खड़ा करके क्षेत्रीय दलों को रैटैंड लेने के लिए मजबूर करने का सियासी दांव खेला है। वहीं दूसरा मौका जीएसटी के मामले पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रहे टकराव को लेकर है। केंद्र की ओर से आर्थिक संकट के बीच उचित मदद नहीं मिलने की बात लगभग सभी विपक्षी राज्य उठा रहे हैं। अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस संसद में इस मसले को उठाएंगी। इन मसलों पर अपने राज्य का हित छोड़कर केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना इन नेताओं के लिए आसान नहीं होगा।

